हस्तशिल्प उद्योग ने परम्परा व पहचान का संरक्षण किया है- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने जोधपुर में पश्चिम राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव-2026 का उद्घाटन किया

जोधपुर, 26 दिसम्बर (कासं)। शुक्रवार को जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हस्तशिल्प उद्योग ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण का माध्यम है तथा इसने परंपरा और पहचान का संरक्षण किया है। यह श्रमिकों,

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने हस्तशिल्पियों को सहायता देने के लिए 1,197 दस्तकार परिचय पत्र जारी किए। राज्य सरकार बुनकर पुरस्कार योजना, बाज़ार सहायता योजना व चर्म प्रशिक्षण योजना से हस्तशिल्पियों को लाभ पहुँचा रही है।**

महिलाओं, युवाओं और गरीबों के स्वावलंबन का माध्यम भी बना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हस्तशिल्पियों के कल्याण को सर्वोपरि माना है। हमारी सरकार ने हस्तशिल्पियों को सहायता देने के लिए 1,197 दस्तकारों को परिचय पत्र जारी किए हैं। राज्य सरकार द्वारा बुनकर पुरस्कार योजना, बाजार सहायता योजना एवं चर्म प्रशिक्षण योजना से विभिन्न हस्तशिल्पियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। साथ ही, माटी कला कामगारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीनें भी दी गई हैं। पी.एम. विश्वकर्मा योजना के तहत, कारपेंटर, मूर्तिकार, कुम्हार, राजमिस्त्री सहित, 18 ट्रेड्स के दस्तकारों को 5 प्रतिशत ब्याज पर ऋण के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निर्यात को 1.50 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी अधिसूचित की गई। एक जिला-एक उत्पाद पहल के तहत, राजस्थान ओडीओपी नीति तथा राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 को फरवरी 2025 को लागू किया गया। शर्मा ने कहा कि हमने राज्य के विकास का रोडमैप बनाकर कार्य किया है। पानी-बिजली की प्राथमिकता को सर्वोपरि रखते हुए इस क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल,उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भी संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लघु उद्योग भारती स्मारिका का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने पंच गौरव प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

जाँच समिति ने इंडिगो संकट पर रिपोर्ट सौंपी

नयी दिल्ली, 26 दिसंबर। इंडिगो संकट की जांच के लिए गठित चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी।

सरकार ने दिसंबर के पहले सप्ताह में इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द होने के बाद जांच के लिए 05 दिसंबर को एक समिति का गठन किया था। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में संयुक्त महानिदेशक संजय के. ब्राम्हणे की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस समिति के अन्य सदस्यों में डीजीसीए के उप महानिदेशक अमित गुप्ता, वरिष्ठ फ्लाइट ऑपरेशन्स इंस्पेक्टर (एफओआई) कैप्टन कपिल मांगलिक और एफओआई लोकेश रामपाल शामिल थे।

समिति को इंडिगो के परिचालन में बड़े पैमाने पर हुए व्यवधान के कारणों की जांच की जिम्मेदारी दी गयी थी। साथ ही उसे भविष्य में इस तरह के संकट को रोकने के उपाय सुझाने के लिए भी कहा गया था। समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। समिति ने शुक्रवार शाम अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

उत्तर प्रदेश एसआईआर में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटेंगे

चुनाव आयोग ने कहा 31 दिसम्बर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी

- **जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटेंगे उनमें से 1.26 करोड़ अपनी जगह पर नहीं मिले, 46 लाख मृत पाए गए, 23.37 लाख डुप्लीकेट मतदाता मिले, 83.73 लाख अनुपस्थित रहे, वहीं 9.97 लाख अन्य श्रेणियों के वोटर्स हैं।**

लखनऊ, 26 दिसंबर। वोटर्स के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं। बता दें कि यूपी की वोटर लिस्ट में अभी तक 15.44 करोड़ नाम थे, लेकिन अब इसमें करीब 3 करोड़ वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे, उनमें 1.26 करोड़ वोटर्स अपनी जगहों पर नहीं मिले। इसके अलावा, 46 लाख मृत पाए गए, जबकि 23.70 लाख वोटर्स डुप्लिकेट मिले। वहीं 83.73 लाख लोग अनुपस्थित मिले, जबकि 9.57 लाख अन्य कैटेगरी के वोटर्स हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसके पब्लिश होने के बाद, से लेकर 30 जनवरी, 2026 तक दावे-आपत्तियां स्वीकार किए जाएंगे। सभी जांच-पड़ताल के बाद 28 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी।

चुनाव आयोग के मुताबिक, यूपी में मैपिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है, यानी साल 2003 की वोटर लिस्ट से वर्तमान वोटर लिस्ट का मिलान किया गया, जिसमें लगभग 91 प्रतिशत लोगों का डेटा मिलान हो चुका है। ऐसे वोटर्स के नाम उनके रिलेटिव्स जैसे मां-बाप, दादा-दादी या नाना-नानी से मिलाया गया है।

बाकी 9 प्रतिशत यानी, 1.11 करोड़ वोटर्स को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा। जिन्हें अब अपनी पहचान साबित करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग को देने होंगे।

उत्तर प्रदेश में फिलहाल 11 लाख से ज्यादा लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म भर चुके हैं। जिन लोगों की उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 साल पूरी हो रही है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बता दें कि एसआईआर के लिए यूपी के तमाम जिलों में विशेष कैंप लगाए गए। मतदान केन्द्रों पर बीएलओ को तैनात किया गया था। इसके अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि, बीएलए ने एसआईआर गणना फॉर्म को भरवाने में मदद की।

लखनऊ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आलोचना दो तर्कों पर आधारित है। पहला, जैसा कि कांग्रेस नेता उदित राज और अन्य विपक्षी नेताओं ने कहा है, भाजपा ने तीन ब्राह्मण नेताओं को चुना, जिनमें से दो तो इस राज्य के निवासी ही नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से थे, जबकि वाजपेयी भी, हालांकि वे उत्तर प्रदेश को अपनी "कर्मभूमि" मानते थे, संयुक्त मध्य प्रदेश के थे। सोशल मीडिया पर यह सवाल भी गर्मा रहा है: भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की विरासत को क्यों नज़रअंदाज़ किया, जिनके कार्यकाल में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी? संयोग की बात है कि जिस क्षेत्र में यह स्मारक स्थापित किया गया है, उसके चारों तरफ बसे गाँवों में लोध जाति का बाहुल्य है तथा कल्याण सिंह भी इसी जाति से थे। एक अन्य चर्चित सवाल यह है: एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जिन्हें अयोध्या आंदोलन का शिल्पी माना जाता है, इस कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाए गए?

रेगिस्तान को आगे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार बोलती है कि 100 मीटर की पहाड़ी को अरावली पर्वत माना जाएगा। उसके नीचे वाली पहाड़ियों को अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा। सचिन पायलट ने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए कहा, इन चारों राज्यों में अरावली श्रृंखला में जो पर्वत आते हैं, उनमें से 118000 पर्वत 100 मीटर से कम हैं। 100 मीटर से ज्यादा सिर्फ 1048 पहाड़ हैं। उन्होंने कहा कि चतुराई से कोर्ट से अरावली की पर्वत की परिभाषा को बनवाया गया है। खनन पर बैन लगाने से कुछ नहीं होता, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा, सरकार बोल रही है हम राज्य को नुकसान नहीं होने देंगे। अरे नुकसान तो हो रहा है। अवैध खनन चल रहा है। आंकड़ों के जाल में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। एनसीआर में कितना प्रदूषण है। इससे कितना नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को ये पहाड़ ही रोकते हैं। ये बात 100 मीटर की नहीं है ये बात आने वाली 100 पीढ़ियों की है। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट बोले, आज इस बात पर देश और दुनिया की नजर टिकी है कि राजस्थान और हरियाणा में जो अरावली की पर्वतमाला है, इसके वर्तमान और भविष्य में क्या हाल हैं। अरावली पर्वतमाला सिर्फ एक पहाड़ों का समूह नहीं है। अरावली पूरे उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से को सुरक्षित रखती है। रेगिस्तान पश्चिमी भाग से लगातार हमारी तरफ बढ़ता या पूर्व की तरफ जाता है। उसको अरावली की पहाड़ों ने रोका हुआ है। मानसून हो, खेत खलियान हो, जमीन, पानी हो, जानवर, पशु, पूरे पर्यावरण में लाखों करोड़ों लोगों के लिए सुरक्षा कवच बनकर अरावली पर्वतमाला खड़ी है।

अमेरिका का नाइजीरिया के आईएस ठिकानों पर अटैक

वाशिंगटन, 26 दिसंबर। अमेरिका ने नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले किये और उनकी शिविरों को निशाना बनाया है। यह जानकारी अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने दी है। अमेरिकी सेना के अनुसार, ये हमले सोकोतो राज्य में नाइजर के साथ लगी नाइजीरिया की सीमा के पास समूह द्वारा संचालित ठिकानों पर किए गये। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती आकलन से पता चला है कि कई आतंकवादी मारे गए हैं, हालांकि नुकसान की पूरी जानकारी का अभी भी मूल्यांकन किया जा रहा है।

कुलदीप सेंगर को जमानत देने के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुँची

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है

- **सीबीआई ने कहा, सेंगर को जमानत मिलने से न्याय प्रक्रिया व पीड़िता की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।**
- **पीड़िता की मां ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही।**

नई दिल्ली, 26 दिसंबर। सीबीआई ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार(16 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित करते हुए जमानत दे दी गई थी।सीबीआई का कहना है कि सेंगर को जमानत मिलने से न्याय प्रक्रिया और पीड़िता की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस याचिका पर सुनवाई करेगा।

इससे पहले शुक्रवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मां सहित महिला कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े कई लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद किया गया। पीड़िता की मां ने शुक्रवार को कहा थाकि वह दोषी कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी।

पीड़िता की मां ने भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पीड़िता की मां ने कहा कि वह अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय के विरोध में यहां आई हैं।उन्होंने कहा, मैं पूरे हाईकोर्ट को दोष नहीं देती, लेकिन दो न्यायाधीशों के फैसले से हमारा भरोसा टूट गया है और मुझे गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पहले न्यायाधीशों ने उनके परिवार को न्याय दिलाया था, लेकिन अब आरोपी को जमानत दे दी गई है।पीड़िता की मां ने कहा, यह हमारे परिवार के साथ अन्याय है। हम उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे, मुझे उस पर पूरा विश्वास है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीपसेंगर की उम्रकैद की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया था। कोर्ट ने सेंगर को सख्त शर्तों के साथ जमानत दी, जिसमें पीड़िता के निवास से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखना, पीड़िता या उसके परिवार को धमकी न देना और 15 लाख रुपये का मुचलका जमा करना शामिल है। सेंगर ने करीब साढ़े सात साल जेल में बिताए हैं। हालांकि, पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के अलग मामले में 10 साल की सजा के कारण सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आ सके हैं।

डॉ. मनमोहन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने देश के आर्थिक विकास को जो दिशा दी वह भारत की समृद्धि का मजबूत आधार बन गया है। खड़गे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर डॉ सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा "पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर, हम भारत के राष्ट्र निर्माण में उनके अपार योगदान को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। एक परिवर्तनकारी नेता के रूप में, उन्होंने देश के आर्थिक पथ को नया रूप दिया और आर्थिक सुधारों के माध्यम से लाखों लोगों के लिए अवसरों का विस्तार किया तथा लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। राहुल ने कहा "डॉ. मनमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। अपने दूरदर्शी नेतृत्व से उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त किया। देश के वंचितों और गरीबों के लिए उनके ऐतिहासिक प्रयासों और साहसिक निर्णयों ने भारत को विश्व मंच पर एक नई पहचान दिलाई।" प्रियंका ने कहा "भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री एवं रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ मनमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। डॉ सिंह समानता में विश्वास रखने वाले, दृढ़ निश्चयी, साहसी और गरिमापूर्ण व्यक्तित्व की मिसाल थे, जो सच्चे अर्थों में देश की प्रगति के लिए समर्पित रहे।"

गैंग रेप का आरोपी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गैंग रेप किया गया। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ उदयपुर, माधुरी वर्मा के नेतृत्व में सुखेर थानाधिकारी रविन्द्र चारण मय टीम ने अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार आईटी कंपनी सीईओ जितेश प्रकाश सिसोदिया, पुत्र कचरूलाल सिसोदिया, निवासी स्काई मरीना अपार्टमेंट, अम्बामाता, गौरव सिरोही, पुत्र शक्तिवीर सिंह सिरोही, निवासी पामयीन सुपरटेक यूपी, हाल हितावा अपार्टमेंट, को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर 29 दिसंबर तक के लिए रिमाण्ड पर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों द्वारा गैंग रेप की वारदात करने पर पीड़िता ने तीन दिन पूर्व सुखेर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था।

केरल में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिक हैं। सीपीआईएम के आरपी शिवाजी को 29 वोट मिले और कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ के केएस सबरीनाथन को 19 वोट मिले। एक पार्षद, एक स्वतंत्र विधायक, ने मतदान में भाग नहीं लिया। एक जीत एक अन्य स्वतंत्र पार्षद, पी. राधाकृष्णन के समर्थन से संभव हुई। भाजपा ने दिसंबर 9 के चुनाव में 50 सीटें जीती थीं, जो पार्टी के लिए एक रिकॉर्ड सफलता थी।

16 साल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

टिप्पणी तब की, जब याचिकाकर्ता एस. विजयकुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील केपीएस पलानीवेल राजन ने एक नए आस्ट्रेलियाई कानून का हवाला दिया और कहा भारत को भी ऐसा कानून लागू करना चाहिए।

20 बहादुर बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरुस्कार

- **राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में ये पुरुस्कार प्रदान किए**

नयी दिल्ली, 26 दिसंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में 18 राज्यों के 20 साहसी बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है।

मुर्मू ने शुक्रवार को यहां विज्ञान भवन में एक समारोह में इन बच्चों के उनके असाधारण कार्यों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये। राष्ट्रपति ने पुरस्कार पाने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि पुरस्कार विजेता बच्चों ने अपने परिवारों, अपने समुदायों और पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मान पाने वाले इन बच्चों से देश के अन्य सभी बच्चे प्रेरित होंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि लगभग 320 वर्ष पूर्व, सिख पंथ के दसवें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोबिन्द सिंह जी और उनके चारों बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिया था। इस दिन हम सब उनके दो सबसे छोटे साहिबज़ादों का स्मरण करते हैं, जिनकी वीरता का सम्मान देश-विदेश में किया जाता है।

मुर्मू ने कहा "मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि सभी पुरस्कार विजेता बच्चों ने अलग-अलग क्षेत्रों में असाधारण योगदान किये हैं। वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवोचार, विज्ञान तथा तकनीकी, समाज-सेवा और खेल-कूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपकी असाधारण बाल-प्रतिभा का परिचय प्राप्त हुआ है।"

उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पुरस्कार पाने वाले बच्चों ने वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उनका कहना था कि सात वर्षीय वाका लक्ष्मी प्रग्निका जैसे प्रतिभाशाली बच्चों के कारण ही भारत विश्व पटल पर शतरंज की महाशक्ति माना जाता है। अजय राज और मोहम्मद सिदान पी. ने अपनी वीरता और सूझबूझ से दूसरों की जान बचाकर अत्यंत प्रशंसनीय काम किया है। इसी तरह से नौ वर्षीय बेटी व्योमा प्रिया और ग्यारह वर्षीय बहादुर बेटे कमलेश कुमार ने अपने साहस से दूसरों की जान बचाते हुए अपने प्राण गंवा दिए।

राष्ट्रपति ने कहा कि यह गौरव की बात है कि दस वर्षीय श्रवण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध से जुड़े जोखिमों के बावजूद, अपने घर के पास सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों को नियमित रूप से पानी, दूध और लस्सी पहुंचाई। वहीं, दिव्यांग बेटी शिवानी होसुरू उप्पारा ने आर्थिक और शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए खेल जगत में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अत्यंत प्रतिस्पर्धी और प्रतिभा-समृद्ध क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है और कई रिकॉर्ड स्थापित किए।

महाराष्ट्र की राजनीति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **कांग्रेस तो अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है और अब सबकी नज़र एनसीपी पर है, वैसे एक चर्चा यह भी है कि अपनी क्षमता आंकने के लिए हो सकता है, अजीत पवार अकेले चुनाव लड़े।**

एनसीपी विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल हो गये थे, और इसके बदले में वे उपमुख्यमंत्री बनाए गए थे। लेकिन अब वे भाजपा नेतृत्व वाले सत्तारुढ़ महायुति गठबंधन में हाशिये पर हैं।

अजित पवार ने एनसीपी मुंबई चुनाव अभियान में अपनी पार्टी के चेहरे के रूप में पूर्व मंत्री नवाब मलिक का नाम दिया था, जिसे भाजपा ने सख्ती से नकार दिया। भाजपा ने उन्हें माफिया सरगना दाऊद इब्राहीम से कथित संबंधों के आधार पर खारिज किया।

वास्तविक कारण यह था कि अजित पवार की एनसीपी को मुस्लिम और दलित मतदाताओं से जो समर्थन मिलता, वह भाजपा के कट्टर हिंदू आधार को नाराज कर सकता था।

इस बीच, एक अन्य पारिवारिक पुनर्मिलन में शरद पवार खुद को तीसरे पहिये के रूप में पा रहे हैं। ठाकरे बंधु, उद्धव और राज, जो शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के निधन के बाद 20 सालों तक एक-दूसरे से विरोध में रहे थे, मराठी भाषा के विवाद पर एकजुट हो गये और गठबंधन का ऐलान कर दिया।

लेकिन इस समय तक, शरद पवार और कांग्रेस में से कोई भी राज ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि वह बीएमसी चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और शरद पवार की एनसीपी को एमवीए के सीट-बंटवारे की बातचीत से बाहर कर दिया गया है।

मजेदार बात यह है कि दोनों गठबंधन एनसीपी के दोनो गुटों पर ध्यान जमाये हुए हैं।

क्या इसका मतलब यह है कि चाचा भतीजा एक हो रहे हैं? या अजित पवार 'अकेले चलने' की योजना बना रहे हैं?

इस बारे में चर्चा हो रही है कि बाद वाला विकल्प संभावित है। सूत्रों ने कहा कि इस चुनाव में हार को एक धक्के के रूप में नहीं देखा जाएगा; विचार यह है कि अजित पवार की एनसीपी की ताकत का आकलन एकल मुकाबले में ही किया जाए।

वर्ष 2024 के राज्य चुनाव में उनकी एनसीपी ने 59 सीटों में से 41 सीटें जीतीं, जो एक शानदार परिणाम था। इससे कुछ माह पहले पार्टी लोकसभा चुनाव में हार गई थी, और केवल चार सीटों में से एक ही जीत पायी थी। यदि ऐसा ही परिणाम फिर से आता है, तो यह अजित पवार को घर वापसी पर विचार करने के लिए तैयार कर सकता है। हालांकि इसके लिए दोनों गुटों के मंत्रियों और विधायकों को खुश रखने के लिए व्यापक बातचीत की आवश्यकता होगी।

गुरुवार रात, अणुशक्तिनगर में, जो नवाब मलिक की विधायक बेटी सना मलिक का विधानसभा क्षेत्र है, अजित पवार ने शरद पवार के पोते रोहित पवार से मुलाकात की। पुणे नगर निगम चुनाव के लिए एक समझौता हुआ, हालांकि सीटों के बंटवारे पर कोई बात नहीं हुई।

लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि शरद पवार के गुट की ओर से 'घड़ी' चुनाव चिन्ह का फिर से उपयोग करने की मांग का बयान सामने आया था, जिस पर विवाद उस समय सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया था, जब यह अजित पवार को आवंटित कर दिया गया था।

यह बयान इस संभावना को बल दे रहा है कि पवार परिवार पुनर्मिलन की पटकथा लिख रहा है।

दिल्ली में 13 राजस्व जिले बने

नई दिल्ली, 26 दिसंबर। दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक नक्शे को नए सिरे से गढ़ते हुए 13 राजस्व जिलों की व्यवस्था लागू कर दी है। इससे राजस्व जिलों और नगर निगम जोन की सीमाएं एक समान हो गई हैं, जो अब तक प्रशासनिक कामकाज में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थीं। सरकार का दावा है कि इस फैसले से शासन अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनता के करीब होगा।

राजस्व जिलों और नगर निगम ज़ोन की अलग-अलग सीमाओं के कारण अधिकारियों और आम नागरिकों दोनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब सीमाएं एक जैसी होने से अधिकार क्षेत्र को लेकर भ्रम खत्म होगा और फाइलों के चक्कर भी कम होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह समस्या दशकों से लंबित थी, जिसे उनकी सरकार ने केवल 10 महीनों में सुलझा दिया। भाजपा सरकार ने जून महीने में 11 नगर निगम ज़ोन की जगह 13 राजस्व जिले बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद इस प्रस्ताव पर लगातार काम चलता रहा। 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक बुलाकर इसे अंतिम मंजूरी दी। उपराज्यपाल वी के सक्सेना की सहमति के बाद अब इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

बेगम ज़िया की पार्टी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **भारत के लिए अटपटी स्थिति है, क्योंकि, अंतरिम सरकार कट्टरपंथी रूढ़िवादी ताकतों के नियंत्रण में है तथा मोहम्मद युनूस स्वयं कोई स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं तथा सेना भी काफी हद तक कट्टरपंथियों के प्रभाव में है।**
- **अंतरिम सरकार, कानून-व्यवस्था या हिंसा पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, इससे हिन्दू ही नहीं आम जनता भी त्रस्त है और अव्यवस्था के कारण, बांग्लादेश अपने टैक्सटाइल के ऑर्डर समय से सप्लाई नहीं कर पा रहा है। टैक्सटाइल निर्यात ही बांग्लादेश की इकॉनमी का आधार है। अगर यह आधार डगमगाया तो बांग्लादेश को भारी झटका लग सकता है।**
- **पर, भारत पर आंतरिक दबाव है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही खुल्लम-खुल्ला हिंसा व लूटपाट के खिलाफ कुछ न कुछ अवश्य करे। कुछ करने के लिए भारत की मजबूरी बढ़ रही है।**

बीएनपी की स्थिति काफी नाज़ुक है। एक तरफ वह मुख्यधारा की पार्टी बनकर चुनाव लड़ने और दूसरी तरफ अन्य राजनीतिक संगठनों का सिर्फ एक हिस्सा बनकर रहने के बीच फँसी हुई है, क्योंकि एक तरह से, बीएनपी कट्टरपंथी इस्लामवादियों और मध्यमार्गी मुख्यधारा की पार्टियों के बीच में फंस गई है।

चूँकि, अंतरिम सरकार ने अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया है, इसलिए चुनाव एक अजीब और एकतरफा हो गया है, जहाँ ज़्यादातर मुकाबला ज़्यादा कट्टरपंथी और छोटे दलों के बीच रह गया है। इस राजनीतिक माहौल में बीएनपी कहीं खो सी जाती है, हालांकि शहरी इलाकों में वह अब भी अपने पाँव जमाने की कोशिश कर रही है। पार्टी को बरसों तक बेगम ज़िया ने काफ़ी कुशलता से चलाया था, उस समय भी जब वह सत्तारूढ़ अवामी लीग की कार्रवाईयों का सामना कर रही थी। यह मानना पड़ेगा कि अपने सुनहरे दिनों में अवामी लीग भी राजनीतिक विरोधियों के साथ निपटने में बहुत निष्पक्ष नहीं थी।

लेकिन जब अंतरिम सरकार ने अवामी लीग को चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित किया था, तब बीएनपी ने इस प्रतिबंध को हटाने की माँग की थी और अवामी लीग की चुनाव में भागीदारी का समर्थन किया था, हालांकि बाद में पार्टी का रुख कुछ ठंडा पड़ गया और अवामी लीग के प्रति सख़्त विरोध के संदर्भ में पार्टी कुछ हद तक नरम पड़ गई।

मौजूदा परिदृश्य में अंतरिम सरकार पर कट्टरपंथी गुटों का सख़्त दबाव है। मोहम्मद यूनुस अपने स्तर पर फ़ैसले नहीं ले पा रहे हैं और सेना भी किसी हद तक कट्टरपंथियों के प्रभाव में दिखाई दे रही है।

लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश की स्थिति बिगड़ती जा रही है, वह भारत के लिए भी एक कठिन स्थिति बन सकती है। बांग्लादेश में बढ़ती असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं, की हत्याओं के कारण भारत के लिए इन घटनाक्रमों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करना मुश्किल हो रहा है। ये भारत के लिए गंभीर उकसावे हैं और देर-सबेर कोई ऐसा मोड़ आ सकता है जो भारत को कार्रवाई के लिए मजबूर कर दे।

एक तो, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार देश में हिंसा और आगज़नी को काबू में करने में अपनी बेबसी दिखा रही है। बिगड़ती क़ानून-व्यवस्था न सिर्फ़ अल्पसंख्यकों बल्कि पूरी आबादी के लिए ख़तरा बनती जा रही है।

इसके साथ ही आर्थिक हालात भी बिगड़ रहे हैं और बांग्लादेश कपड़ा निर्यात के अपने सप्लाई अनुबंधों की समय-सीमा पूरी करने में नाकाम हो रहा है। यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है और अगर कपड़ा उद्योग चरमरा गया तो पूरी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लग सकता है।

ऐसे हालात में भारत, बांग्लादेश के लिए ज़रूरी सप्लाई रूट और कुछ अहम लॉजिस्टिक जीवनरेखाओं को रोक कर उसके लिए गंभीर मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

अब देखना होगा कि भारत, बांग्लादेश के बढ़ते भारत-विरोधी रुख और हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्याओं के साथ कब तक संयम रख पाता है। भाजपा पर भी भीतर से दबाव बढ़ रहा है कि कम से कम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालयः राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908